

अडाणी को कलीन चिट मिलने के बाद क्या अब हिंडनबर्ग और राहुल गांधी माफी मांगेंगे



नीरज कुमार दुबे

हम आपको याद दिला दें
कि हिंडनबर्ग ने अपने
तथाकथित इसर्च रिपोर्ट
में अडाणी समूह पर
स्टॉक मैनिपुलेशन और
फर्जी अकाउंटिंग के
आरोप लगाए। रिपोर्ट
ऐसे समय में जारी की
गई जब अडाणी
एंटरप्राइज अपना
20,000 करोड़ रुपये का
मेगा पब्लिक ऑफर
लाने जा रही थी।

संपादकीय

लाठी अदालत की

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वियां शुरू होने से पहले तीन सप्ताह के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण रोकने के उपाय पेश करने को कहा है। उप्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों से नाराजगी जाती हो एवं रिक्तियां भरने के लिए छह महाने का समय दिया। वायु गुणवत्ता आयोग केंद्र सरकार का वैधानिक निकाय है जिसका लक्ष्य दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन व सुधार करना है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, उप्र, राजस्थान व पंजाब के हिस्से शामिल हैं, जो प्रति वर्ष सर्वियों में भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। पीठ ने दंड प्रावधानों पर भी जोर दिया। अदालत के बाब-बाब कहने के बाबजूद राज्य सरकारों की तरफ से वायु गुणवत्ता के सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए जाते। आयोग के गठन के बाबजूद समाधान ढूँढ़ने व राज्यों तथा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर परिवर्तनकारी मानक नहीं बनाए गए हैं। सर्वियां शुरू होते ही वाहनों के धूएं, धूल-मिट्टी, कारखानों व पराली जलाने के कारण पर्यावरण पर गहरी चादर छा जाती है जो श्वसन-तंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। वाहन उत्सर्जन मानकों को तय करने सालों-साल से चर्चा हो रही है। किसानों या पड़ोसी राज्यों को इस प्रदूषण का दोषी ठहरा कर दिल्ली अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। निर्माण कार्य रोकने का सीधा असर दिवाड़ी मजदूरों को झेलना पड़ता है। पुराने वाहनों की आवाजाही पर पावंडी से साधारण यात्री की दिक्कतों का अंदाज वातानुकूलित लगजरी कारों में बैठने वाले नहीं लग सकते। फिजल बातें, अपृष्ठ दावों, नौकरशाही व जिम्मेदारी से हाथ झाड़ कर सिर्फ सालों-साल राजनीति की जाती है। बीते साल राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक पांच सौ के पार जाने पर तहलका मच गया था। मगर नागरिकों के हितों की अनदेखी और स्वास्थ्यगत जटिलताओं के प्रति उपेक्षा बरतते हुए सरकारों ने तात्कालिक उपायों पर ही जोर लगाया। ठोस कदम उठाने या संकट से निपटने की तैयारी करने के प्रति सरकारी रैव्या उदासीन बना हुआ है। अदालत से फटकार के बाबजूद संस्थाओं तथा आयोगों के अविवेक, अकर्मण्यता व शक्तिहीनता का खमियाजा अंततः आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। प्रदूषण के चलते सबसे अधिक दुर्शा गरीबों व दिवाड़ी कामगारों की होती है जिस पर विचार करने में सरकार को कोताही नहीं करनी चाहिए।

चिंतन-मनन

अनमोल हैं कड़वे बोल

जिसी ने कहा है कि अंधेरे में माचिस तलाशता हुआ हाथ, अंधेरे में होते हुए भी अंधेरे में नहीं होता, इस तलाश को अपने भीतर निरंतर जीवित रखना कोई साधारण बात नहीं है, परंतु जो लोग सफर की हड्डों को पहचानते हैं, जिन्हें हर मजिल के बाद किसी नए सफर पर चल पड़ने की लत है, उनके भीतर से यह खोज कभी खत्म नहीं होती। अचूक शैली में, अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों को अपनी ही खोज के तौर तरीके बताने वाले राष्ट्रसंत मुनि तरुणसागर जी महाराज की वाणी सहज आकर्षण का विषय बन गई है। ऐसे समय में जब अपने हक में हर खुशी बटोर लेने की अदम्य लालसा लोगों को दुनिया के दुर्घटनाएँ दर्शाते हुए दूर ले जा रही हैं। मुनि श्री दुनिया को खुशी और गम की सही परिभाषा बता रहे हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि वे जहां भी पहुंचते हैं, सबसे पहले वही कहते हैं कि मैं कथा सुनाने नहीं जीवन की व्यथा सुनाने आया हूं। यह व्यथा घर-घर की कहानी है, जिसे एक बड़े आँगने की शक्ति में सामने रखकर मुनि तरुण सागर जी पुकार कर कह उठते हैं कि इसे न तो ठुकराओ, न ही झुटलाने की कोशिश करो, बेहतर यही है कि इस व्यथा के बीच से ही जीवन का रस हासिल कर लो। मुनि तरुण सागर जी के बोल, सुनने वाले को भावित-प्रभावित तो करते ही हैं, उसे झांकझोर कर भी रख देते हैं। उन्हें सुनने समय या पढ़ने समय आप अनुभव करते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी एक धारावाहिक के रूप में आपकी आंखों के सामने तैरने लगी है। उनकी वाणी अतीत की जड़ता से उत्तराने और वर्तमान की लापरवाही के प्रति सचेत करने का काम करती है। वह आपके जख्मों को सहलाने के बदले यदि अधिक कुरदग्धे की मुद्रा में दिख भी रही हो तो भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मुनि श्री आपको स्थाई रूप से तंदुरुस्त बनाने का उद्यम कर रहे हैं। सूत्र शैली में संदेश देने वाले मुनि तरुण सागर जी को अपनी वाणी को कड़वे प्रवचन कहने पर इत्मीनान यदि है तो सिर्फ इसलिए कि वे जानते हैं, इंसान की प्रवृत्ति और कभी न बदलने की उसकी जिद इतनी कठिन और जटिल है कि सीधी उंगली से घी निकालना मुमकिन नहीं है। आज साहित्य, संस्कृति और समाज के हर मंच पर महिला जागृति या नारी विमर्श का दौर ही चल पड़ा है। मुनि तरुण सागर जी साफ शब्दों में कहते हैं कि समाज पुरुष प्रधान है, परंतु याद रखना चाहिए कि महिलाओं की भूमिका पुरुषों से भी बड़ी है। वे सत्य से मुंह मोड़ने या पीछे हटने वाले समाज को न सिर्फ जगाते हैं बल्कि अपने कड़वे बोल से कोसने में भी कोई गुरेज नहीं करते। सच के पांखंडी चेहरे को पहचानने वाली उनकी गहरी दृष्टि सजग करती हैं कि वास्तव में जो सत्य है उसे किसी बनावट की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष में सत्य परेशान हो सकता है किन्तु प्राप्तिजन नहीं होता।

ज नवरी 2023 में अमेरिकी शॉट्स-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों में शुमार अडाणी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों का स्वरूप इतना सनसनीखेज था कि देखते ही देखते शेयर बाजार में भूचाल आ गया। करोड़ों निवेशकों की मेहनत की कमाई रातों-रात ढूब गई और भारत की वैश्विक आर्थिक साख पर प्रश्नचिह्न लगाने की कोशिश हुई। यह केवल एक कॉपरेट विवाद नहीं था, बल्कि भारत की औद्योगिक प्रगति को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश थी।

हम आपको याद दिला दे कि हिंडनबग ने अपने तथाकाथित रिसर्च रिपोर्ट में अडाणी समूह पर स्टॉक मैनपुलेशन और कर्जों अकार्डटंग के आरोप लगाए। रिपोर्ट ऐसे समय में जिसी की गई जब अडाणी एंटरप्राइजेज अपना 20,000 करोड़ रुपये का मेगा पब्लिक ऑफर लाने जा रही थी। इसका सीधा असर यह हुआ कि निवेशकों का विश्वास हिल गया और शेरयों में भारी गिरावट दर्ज हुई। चिंता की बात यह थी कि भारत के कुछ विपरीती दलों ने भी इस रिपोर्ट को सच मानकर इतना दुष्प्राचार किया मानो पूरा अडाणी समूह भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा हो। संसद से लेकर सड़क तक इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई। इस राजनीतिकरण ने विदेशी निवेशकों में भी भ्रम फैलाया और भारत के कॉर्पोरेट जगत की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचा।

लेकिन लगभग दो साल की लंबी और गहन जाँच के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने साफ कह दिया है कि अडाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप

निराधार और आधारहीन थे। जाँच में पाया गया कि जिन वित्तीय लेन-देन को हिंडनबर्ग ने 'फर्जी' बताया, वे सब कानूनी रूप से वैध ऋण और पुनर्भुगतान थे। न तो धन का गवन हुआ, न ही किसी अवैध पार्टी को फायदा पहुँचाया गया। यहाँ तक कि जाँच के दौरान लिए गए सभी ऋण ब्याज समेत वापस किए गए। SEBI ने अपने आदेश में यह

A close-up photograph of a man with dark hair and a mustache, wearing a blue suit jacket over a light blue shirt. He is gesturing with his right hand, palm facing up, while speaking. The background is a wooden panel wall.

भी कहा कि इन लेन-देन को 'रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन' या 'फजीवांड़ा' नहीं कहा जा सकता। यानी, आरोपों का कोई बनानी या आर्थिक आधार ही नहीं था। देखा जाये तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते जो हुआ, वह किसी भी देश के उद्योग जगत के लिए चेतावनी है। अडाणी समूह के शेयरों में अचानक भारी गिरावट आई। छोटे-बड़े कराड़ों निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। यह नुकसान केवल अडाणी का नहीं था, बल्कि भारत के वित्तीय बाजार और निवेश माहौल का भी था। गौतम अडाणी ने स्वयं कहा कि इस विवाद से उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि आम निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह कथन उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाता है और यह भी बताता है कि एक सुनियोजित झूठ कितनी बड़ी आर्थिक तबाही ला सकता है। देखा जाये तो हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट मात्र एक रिसर्च डॉक्यूमेंट नहीं थी। यह स्पष्ट था कि इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ छिपे हुए थे। एक तरफ अमेरिकी और पश्चिमी ताकतें भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और उसके वैश्विक प्रभाव से चिंतित थीं, दूसरी तरफ कुछ घेरेलू राजनीतिक दलों ने इसे अपने लाभ के लिए हाथियार बना लिया। इस साजिश का परिणाम यह हुआ कि भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश हुई। विदेशी मीडिया ने भी इस विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया। परंतु समय ने साबित कर दिया कि यह सब केवल भारत

1 2 3 4 5 6 7 8 9

मोदी-ट्रंप के सार्थक संवाद से क्या राह बदलेगी?



सड़क सुरक्षा : व्यवस्था की पोल खोलते हाद

आपातकालीन सेवाएं अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 1,55,622 सँडक मौतें हुई जिनमें से 69,240 दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं। सँडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2022 में 4,64,910 दुर्घटनाओं में 1,47,913 मौतें हुईं। समस्या यह है कि भारत में एंबुलेंस सेवाएं जैसे 108 या 102, अक्सर आवरलोड होती हैं। ग्रामीण और राजमार्गीय इलाकों में तो स्थिति और भी खराब है। यहां एंबुलेंस पहुंचने में औसतन 45 मिनट से एक घंटा लग जाता है।

एक अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना स्थल से ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने में देरी से 40 प्रतिशत मौतें बढ़ जाती हैं। दिल्ली में, जहां वाहनों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, ट्रैफिक जाम एंबुलेंस को रोक देता है। फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्री-हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर मजबूत होती तो 30-50 प्रतिशत जानें बच सकतीं। लेकिन सरकार की 'ई' रणनीति-इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, में इमरजेंसी केयर पर निवेश न्यूनतम है। नतीजा? हर दिन 405 मौतें और 1,290 घायल। यह राष्ट्रीय संकट है।

गांतारान नियमों की अवहेलना की बात करें। इमरजेंसी सेवाएं अवहेलना की बात करें। अपातकालीन सेवाएं अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 1,55,622 सँडक मौतें हुई जिनमें से 69,240 दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं। सँडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2022 में 4,64,910 दुर्घटनाओं में 1,47,913 मौतें हुईं। समस्या यह है कि भारत में एंबुलेंस सेवाएं जैसे 108 या 102, अक्सर आवरलोड होती हैं। ग्रामीण और राजमार्गीय इलाकों में तो स्थिति और भी खराब है। यहां एंबुलेंस पहुंचने में औसतन 45 मिनट से एक घंटा लग जाता है।

एक सर्वे के अनुसार, अधिकांश ड्राइवरों को नियमों की पूरी जानकारी ही नहीं है। परिणामस्वरूप, 2021 में 35,000 पैदल यात्री और 10,000 बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार बने। जनता जागरूक होती, तो ये आंकड़े कम होते। इस अवहेलना का एक प्रमुख कारण है कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुस्ती भी है। ट्रैफिक पुलिस की कमी भयानक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार, 85,144 ट्रैफिक पुलिस पदों में 30 प्रतिशत और 58,509 कांस्टेबल पदों में 39 प्रतिशत रिक्त हैं। बिना सख्ती के, लोग नियम तोड़ते हैं। क्यों आलसी हैं एजेंसियां? फहल संसाधनों की कमी। कैमरे, स्प्रीड गन्स, बॉडी कैम आदि जैसे उपकरण आर्गामित हैं। गोटर ट्रैकल गति-

की औद्योगिक क्षमता को चोट पहुँचाने का प्रयास था। अब जबकि सेबी की रिपोर्ट ने सभी आरोपों को झूठा सिद्ध कर दिया है, तो सबसे पहला कर्तव्य हिंडनबर्ग और उनके समर्थकों का बनता है कि वे भारत और निवेशकों से माफी मांगें। इसके साथ ही, भारत के विपक्षी दलों को भी आत्मवंथन करना चाहिए कि क्या केवल राजनीतिक विरोध के लिए वे ऐसी अंतरराष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा बन सकते हैं? लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जरूरी है, लेकिन जब बात राष्ट्रहित और निवेशकों के विश्वास की हो, तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च तो अपनी कंपनी बंद कर चुका है, लेकिन उसकी अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर देश की संसद का पूरा सत्र ठप करने वाले विपक्षी दल आज भी सक्रिय हैं। उस समय जिस तरह से उन्होंने निराधार आरोपों को हवा दी, विदेशी एजेंड को ताकत दी और करोड़ों निवेशकों के भरोसे को चोट पहुँचाई, वह केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के साथ खिलबाड़ था। आज जबकि सच सामने आ चुका है और नियामक संस्था ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, विपक्षी दलों को कम से कम देश और जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहुग्रहात् हिंडनबर्ग पक्षण ने हमें यह मिग्रावा है कि

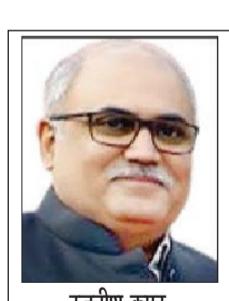
किसी विदेशी रिपोर्ट या आरोप को अँख मूँदकर सच नहीं मान लेना चाहिए। इस मामले ने करोड़ों निवेशकों को झकझोरा, अडाणी समूह की छवि को धक्का पहुँचाया और भारत की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी। परंतु अंततः सच्चाई सामने आई और स्पष्ट हुआ कि यह सब एक रचा-बसा बद्यन्त्रथा। अब समय आ गया है कि न केवल हिंडनबर्ग, बल्कि इस साजिश में शामिल राजनीतिक ताकतें भी देश और निवेशकों से सार्वजनिक रूप से माफी माँगें। क्योंकि भारत की औद्योगिक प्रगति किसी एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। और उस पर चोट करना सीधे-सीधे राष्ट्रहित पर चोट करना है।

अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग आने वाले दशकों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं। चाहे राजनीति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या तकनीक-भारतीय-अमेरिकी समुदाय का योगदान उल्लेखनीय है। यह समुदाय भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को भावनात्मक और सांस्कृतिक आधार देता है। ट्रंप और मोदी की बातचीत में भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रशंसना भी हुई, जिसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सम्पर्क को बढ़ाया।

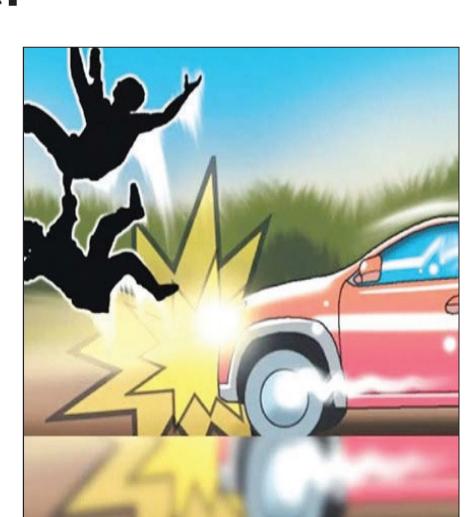
निकटता का आर बढ़ाया। भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। 9/11 की घटना ने अमेरिका को और 26/11 ने भारत को गहरे जख्म दिए। यही कारण है कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों का विट्कोप काफी हद तक समाप्त है। हाल की बातचीत में आतंकवाद को समाप्त करने और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान और मध्य-एशिया की परिस्थितियों को देखते हुए भारत और अमेरिका का सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक हो सकता है। टूंप और मोदी की बातचीत ने यह साबित किया है कि अंतत के मतभेद रिश्तों का अंत नहीं, बल्कि नए संवाद का अवसर बन सकते हैं। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और आतंकवाद जैसे क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी है। आज जब दुनिया वैश्विक महामारी, आर्थिक संकट, युद्ध की विरोधिका और भू-राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है, भारत और अमेरिका की साझेदारी नई दिशा और स्थिरता का संकेत देती है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार-वार्ता में बेशक व्यवधान आए हों, पर भारत और युरोपीय संघ के बीच जिस गति से वार्ता हो रही है, उससे वर्ष के अंत तक दोनों में व्यापार समझौता होने की पूरी उम्मीद है। असल में दोनों देशों के बीच पांच दौर की व्यापार वार्ता हो चुकी है, लेकिन 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद छठे दौर की प्रस्तावित वार्ता रुक गई थी, जो बीते मंगलवार से फिर पटरी पर लौट आई है। दरअसल, टूंप प्रशासन चाहता है कि भारत अपने कृषि एवं डेवरी क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोले, लेकिन भारत के लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि यह उसके किसानों व मछुआरों के हितों के खिलाफ है। भारत पहले ही कह चुका है कि वह किसानों, डेवरी उत्पादकों एवं सामाजिकर्त्ता के लिए से दर्जे सार्वजनिक तरीफ करेगा।

सड़क सरक्षा : व्यवस्था की पोल खोलते हाउसें



दि ल्ली-भारत की राजधानी-जो तेजी से विकसित हो रही है, में सङ्केतें न केवल प्रगति का प्रतीक हैं, बल्कि मौत का भी सैलाब बन चुकी हैं। 14 सितम्बर, 2025 को दिल्ली में फिर दिल ढहला देने वाली घटना घटी, जब एक बीएमडब्ल्यूकार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत ही हो गई, जबकि उनकी पती गंभीर रूप से यायल हो गई। आए दिन देश के अलग-अलग जगहों पर ऐसी घटनाओं की खबर मिलती हैं, जो देश की सङ्केत सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देती हैं। सङ्केत हादसों के मुख्य कारण हैं-आपातकालीन सेवाओं की कमी, यातायात नियमों की अवहेलना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुस्ती। सबसे पहले, डिल्लिया दुर्घटना को समझें। नवजोत सिंह की मौत के समाप्त में पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी की कार की मृत निर्धारित गति सीमा से काफी अधिक थी। विनिर्दित दृष्टिये के बाद जो मनमें बही लापामाली सापेक्ष



2019 में सख्त जुर्माने जोड़े गए लेकिन ये लागू नहीं होते। दूसरा, ब्रैथाचार, छोटे-मोटे उल्लंघनों पर 50-100 रुपये में सेटलमेंट हो जाता है, जिससे डर समाप्त हो जाता है। तीसरा, प्राथमिकताएं, पुलिस अन्य अपराधों पर फोकस करती है, ट्रैफिक को सेकेंडरी मानती है। चौथा, प्रशिक्षण की कमी, अधिकारी सड़क डिजाइन या व्यवहार समझ नहीं पाते। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खराब सड़क डिजाइन और साइनेज भी दुर्घटनाएं बढ़ाते हैं, लेकिन प्रवर्तन कमज़ोर है। विदेशों की तरह यदि भारत में भी सख्ती हो, तो सुधार संभव है। नवजोत सिंह जैसी मौतें हमें झकझोटाती हैं, यदि हम नहीं चेते, तो और कितने परिवार बिनारेंगे? (लेकर मैं बिज्ञप्ति निजी हूँ)

